विषय: डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए?

कठोर कानून, जागरूकता से ही रुकेगा एआई का दुरुपयोग

कठोरतम कानून बनाना आवश्यक

डीपफेक तकनीक और एआई से प्रस्तुत नकली चेहरे और नकली आवाज का दुरुपयोग राजनीतिक प्रचार, ब्लैकमेलिंग और अफवाह फैलाने में हो रहा है। सरकार को कठोरतम साइबर कानून बनाकर दोषियों को दंडित करना चाहिए। जागरूकता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को डीपफेक पहचानने वाले एल्गोरिद्म विकसित कर एआई का दुरुपयोग रोका जा सकता है।

वर्षा अग्रवाल

भोपाल, मध्य प्रदेश

ऐंटी सॉफ्टवेयर बनाए जाएं

एआई के दुरुपयोग को रोकने वाले ऐंटी सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध होने चाहिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों के लिए सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्था की जाए जिससे लोग इतनी स्वतंत्रता से कोई भी सामग्री किसी की प्रतिष्ठा को खराब करने या धन उगाही के लिए न कर सकें।

डॉ आंजनेय गुप्त

मीरजापुर, उत्तर प्रदेश

सख्त साइबर कानून लागू हो

डीपफेक का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार को सख्त साइबर कानून लागू करना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों को भी एआई आधारित पहचान तंत्र विकसित कर फर्जी सामग्री वाले वीडियो तुरंत हटाने के इंतजाम करने चाहिए। झूठी सामग्री को पहचानने के लिए नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी आवश्यक है। कानून नियंत्रण और तकनीक सुरक्षा से दुरुपयोग रोका जा सकता है।

रमेशचंद्र कर्नावट

उज्जैन,मध्य प्रदेश

निगरानी के लिए एजेंसियां बने

एआई का बढ़ता उपयोग जिंदगी को आसान बनाने के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी, डीपफेक, डिजिटल अरेस्ट आदि को भी बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया पर निजी जानकारियों की उपलब्धता ठगों का काम और आसान करती है। इससे बचाव के लिए पुलिस और संबंधित एजेंसियों को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाए। एआई की मदद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फर्जी वीडियो या पोस्ट का प्रसारण रोकें और ऐप उपलब्ध कराए।

बृजेश माथुर

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

उन्नत तकनीक व कठोर कानून बने

डीपफेक और एआई के खतरों का मुकाबला उन्नत तकनीक, जन जागरूकता और कानून के कठोर अनुपालन से संभव है। डीपफेक सामग्री के स्रोत का पता लगाने के लिए कंप्यूटर फोरेंसिक, सॉफ्टवेयर काफी मददगार हो सकता है। व्यवसायों में स्वेछिक प्रतिबद्धता तथा कानूनी उत्तरदायित्व ढांचे भी डीपफेक खतरों से बचाव में कारगर भूमिका निभा सकते हैं।

ईश्वर चंद गर्ग

कैथल, हरियाणा

डेटा गोपनीयता कानून का पालन

डीपफेक और एआई दुरुपयोग रोकने के लिए अपनी ऑनलाइन उपस्थिति सीमित रखें। एआई तकनीक में भी एआई के नैतिक उपयोग को परिभाषित करने की जरूरत है। डेटा गोपनीयता, पूर्वग्रह और दुरुपयोग सहित एआई के जोखिमों की पहचान करके उन्हें कम करें। जीडीपीआर और सीसीपीए जैसे प्रासंगिक डेटा गोपनीयता कानूनों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करें।

ललित महालकरी

इंदौर, मध्य प्रदेश

नए-नए शोध करने होंगे

डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना, तकनीकी रुप से समाधान करना, नियम और कानून का पालन करवाना, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत सावधानी रखना, शोध और विकास कार्य आदि पर जोर देने जैसे कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा डीपफेक का पता लगाने और इसे रोकने के लिए नए-नए तरीके पर शोध करने की आवश्यक है।

मनमोहन राजावत

शाजापुर, मध्य प्रदेश

कठोर साइबर कानून जरूरी

एआई और डीपफेक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित व बहुस्तरीय कदम जरूरी हैं। सबसे पहले कठोर साइबर कानून और त्वरित दंड व्यवस्था से अपराधियों को तत्काल जवाबदेह बनाया जाए। एआई निर्माताओं पर नैतिक तकनीकी नियंत्रण हो जैसे डीपफेक सामग्री पर अनिवार्य डिजिटल वॉटरमार्क और स्रोत पहचान तकनीक।

कृति जैन

बड़वानी, मध्य प्रदेश

तकनीक और बौद्धिक समझ जरूरी

डीपफेक और एआई का दुरुपयोग आधुनिक समाज के लिए गंभीर नैतिक व तकनीकी चुनौती बन चुका है। इसके नियंत्रण हेतु सख्त कानूनी ढांचा, प्रभावी डिटेक्शन टूल और वॉटरमार्किंग जैसी तकनीकी सुरक्षा आवश्यक है। साथ ही समाज में व्यापक जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना भी जरूरी है ताकि लोग असली और नकली सामग्री की पहचान कर सकें।

अमृतलाल मारू

इंदौर, मध्य प्रदेश

पहचान के टूल विकसित किए जाएं

डीपफेक और एआई से झूठी बातों का प्रचार आम होती जा रही है। इस तकनीक के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने वाले कानून और नियम बनाना अत्यंत आवश्यक है। डीपफेक सामग्री की पहचान करने के लिए डिटेक्शन टूल्स का तेजी से विकास होना चाहिए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर लोगों को डीपफेक के प्रति जागरूक और उसकी पहचान करने में सक्षम बनाना होगा।

भगवानदास छारिया

इंदौर, मध्य प्रदेश

भारतीय कानून का सख्ती से पालन

एआई या सोशल मीडिया का दुरुपयोग होने पर उन पर भारतीय कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। सरकार द्वारा प्रस्तावित नीति कि 10 फीसदी कंटेंट पर स्पष्ट संकेत दिखाए जाएं ताकि यह पता चल सके कि यह एआई निर्मित है, सही कदम है। विदेशों में निर्मित एआई कंटेंट पर भी भारतीय कानून लागू होना चाहिए। इससे डीपफेक करने वालों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

शकुंतला महेश नेनावा

इंदौर, मध्य प्रदेश

तकनीकी उपाय जरूरी

डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए सबसे पहले सख्त कानूनी व्यवस्था आवश्यक है। जो कोई जानबूझकर फेक कंटेंट बनाए या फैलाए, उसे जुर्माना और जेल दोनों की सजा मिलनी चाहिए। तकनीकी दृष्टि से डीपफेक डिटेक्शन टूल्स विकसित किए जाने चाहिए जो वीडियो, ऑडियो और फोटो में बदलाव पहचान सकें। सोशल मीडिया इन टूल्स को अनिवार्य किया जाए।

सुभाष बुड़ावन वाला

रतलाम, मध्य प्रदेश

कानून और नैतिकता से ही संभव

एआई और डीपफेक के दुरुपयोग से बढ़ते ऑडियो-वीडियो से समाज भ्रमित हो रहा है। ऐसे असत्य और निराधार ऑडियो-वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए नवीन कानूनों के निर्माण में विलंब नहीं किया जाना चाहिए और इनकी निरंतर समीक्षा होती रहनी चाहिए।

रामबाबू सोनी

इंदौर, मध्य प्रदेश

सामूहिक जागरूकता आवश्यक

डीपफेक और एआई का दुरुपयोग फेक न्यूज, चरित्र हनन और ब्लैकमेलिंग के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को स्पष्ट नीति और सख्त कानून बनाते हुए सोशल मीडिया को भी संदिग्ध सामग्री हटाने के लिए पर्याप्त सहयोग देना चाहिए। सामूहिक जागरूकता और जिम्मेदार उपयोग से ही इसके दुरुपयोग से रोका जा सकता है।

हीरालाल कर्नावट

अहमदाबाद, गुजरात

सतर्कता से उपयोग ही समाधान

डीपफेक और एआई नये जमाने की गंभीर चुनौतियां हैं। यह प्रौद्योगिकी युद्धनीति या वैश्विक कूटनीति का प्रभावी हथियार बनता जा रहा है। जिस पर बड़ी सावधानी, सतर्कता व बड़ी सूझबूझ के साथ नजर रखने की जरूरत है। इस कार्य में हमें धरातल से जुड़े रिपोर्टर, जांच एजेंसी, संबंधित सरकारी संस्थाओं को विश्वास में लेकर इस घातक प्रभाव पर रोक लगाई जा सकती है।

गजानन पांडेय

हैदराबाद, तेलंगाना

बकौल विश्लेषक

डीपफेक कंटेंट की लेबलिंग अनिवार्य हो

एआई चैटबॉट यूजर को सुविधा के नाम पर यह भ्रम देते हैं कि वे इंटरफेस पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि यहीं से दुरुपयोग शुरू होता है। सरकार को सोशल मीडिया पर डीपफेक कंटेंट की अनिवार्य लेबलिंग और भारतीय अधिकार क्षेत्र में स्पष्ट एआई जनित कंटेंट का ऑडिट ट्रेल रखना चाहिए। मध्यस्थ कंपनियों को नागरिकों, व्यवसायों और सरकार को यह बताना अनिवार्य हो कि किसी कंटेंट को डीपफेक क्यों लेबल किया गया? कॉपीराइट और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की दरकार है। यह कॉपीराइट और ऐट्रिब्यूशन के मुद्दे हल करेगा तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी सवालों व सरकारी मामलों में फैली भ्रांतियों का खंडन करेगा, जहां एआई का दुरुपयोग सबसे हानिकारक है। सरकार को शिक्षा नीति में यह प्राथमिकता देनी चाहिए कि जेनेरेटिव एआई चैटबॉट कैसे नागरिकों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और प्रभावी साक्षरता को कमजोर करते हैं ताकि जनहित में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसका दुरुपयोग करने वालों को सख्त सजा देने की भी आवश्यकता है।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

अभिवर्धन

अध्यक्ष, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ऐंड लॉ

डीपफेक से सावधानी ही बचाव

डीपफेक और एआई से बनाए गए नकली वीडियो या ऑडियो होते हैं जो अविश्वसनीय रूप से असली दिख सकते हैं और सुनाई दे सकते हैं। इससे बचने के लिए अपनी पर्सनल फोटो प्राइवेट रखें। सोशल मीडिया पर जो शेयर करते हैं उसे सीमित करें। स्कैमर डीपफेक बनाने के लिए आपकी इमेज इकट्ठा करते हैं, इसलिए अभी अपनी प्राइवेसी सेटिंग एडजस्ट करें। अपने बैंक अकाउंट और जरूरी ऐप्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें। संदिग्ध कंटेंट की तुरंत प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें और वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अटपटी हरकतों, अजीब पलकें झपकाने, या होंठ जो शब्दों से मेल न खाते हों, उन पर ध्यान दें। डीपफेक में अक्सर ये निशान होते हैं। चैट या ईमेल में संवेदनशील जानकारी शेयर न करें, खासकर फाइनैंशियल डिटेल्स या पासवर्ड। जल्दबाजी में फैसले न लें। स्कैमर जल्दबाजी कराते हैं। अगर दबाव डाला जा रहा है, तो यह शायद एक जाल है। स्मार्ट रहें, सुरक्षित रहें।

बातचीत: सुशील मिश्र

मुकुंद कुलकर्णी

सीईओ - पेपर एडवांटेज

पुरस्कृत पत्र

1

सौरभ गुप्ता

जयपुर, राजस्थान

पुरस्कार राशि
500 रुपये

असली नकली के पहचान के टूल विकसित करने होंगे

एआई और डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे टूल विकसित करने की जरूरत है, जो ये बता सकें कि कोई फोटो, विषयवस्तु, वीडियो एडिटेड या असली है और ये टूल आमजन के लिए सहज उपलब्ध हों। डीपफेक व एआई कंटेंट की लेबलिंग को अनिवार्य किया जाए। दुरुपयोग करने वालों में भय पैदा करने के लिए उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। एआई व डीपफेक के उपयोग को विनियमित करने के लिए विशिष्ट कानून बनना चाहिए। साइबर सुरक्षा मजबूत करने के साथ ही एआई व डीपफेक को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए।

श्रेष्ठ पत्र

ऋषभ देव पांडेय

जांजगीर, छत्तीसगढ़

कठोर कानूनी नियंत्रण और जन जागरूकता जरूरी

डीपफेक और एआई दुरुपयोग समस्या से निपटने के लिए सरकार को कठोर साइबर कानून बनाकर फेक कंटेंट तैयार करने या प्रसारित करने वालों को सख्त दंड देना चाहिए। डेटा सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता संबंधी नियमों को मजबूत करने के साथ ही डिजिटल शिक्षा और जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाकर उन्हें डीप फेक की पहचान करना सिखाया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में एआई नैतिकता के प्रसार की भी जरूरत है। कठोर कानूनी नियंत्रण और जनजागरूकता से ही डीप फेक और एआई के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।

प्रो. आरके जैन

बड़वानी, मध्य प्रदेश

एआई आधारित डिटेक्टर विकसित करने होंगे

डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाएं। सबसे पहले मजबूत कानून बनाएं जो डीपफेक निर्माण और प्रसार को दंडनीय बनाएं जैसे भारत के आईटी कानून में संशोधन। दूसरा, एआई टूल्स में वॉटरमार्किंग और डिटेक्शन एल्गोरिदम अनिवार्य करें, जो फर्जी कंटेंट पहचानें। तीसरा शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही स्कूलों में मीडिया साक्षरता सिखाएं और सोशल प्लेटफॉर्म पर फैक्ट-चेकिंग टूल्स लगाएं। चौथा तकनीकी नवाचार जैसे ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन और एआई-आधारित डिटेक्टर विकसित करें।

देवेंद्रराज सुथार

जालोर, राजस्थान

अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बने वैश्विक मानक

एआई जनित सामग्री पर लेबलिंग और डिजिटल वॉटरमार्किंग अनिवार्य होनी चाहिए। इसके साथ प्लेटफार्म पर ऑटोमैटिक डीपफेक डिटेक्शन सिस्टम और त्वरित टेकडाउन प्रोटोकॉल लागू किए जाने चाहिए। डेवलपर की जवाबदेही सुनिश्चित हो, जबकि स्वतंत्र फैक्ट-चेक नेटवर्क संदिग्ध सामग्री की पुष्टि करें। व्यापक डिजिटल साक्षरता अभियान जरूरी है, ताकि नागरिक नकली सामग्री पहचान सकें। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मानक तय हों और खतरे साझा किए जाएं। कानूनी, तकनीकी, शैक्षिक और कूटनीतिक उपायों का संयोजन ही एआई-दुरुपयोग को प्रभावी रूप से रोक सकता है।

...और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी में आपके विचारों को प्रकाशित करते हैं। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -

वायु प्रदूषण से कैसे निपटा जाए?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:

बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201

या फिर ई-मेल करें

goshthi@bsmail.in

JKCement

A SOLID LEGACY OF TRUST

J.K. Cement Ltd.

CIN No. : L17229UP1994PLC017199

Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208 001 (U.P.)

Ph. : +91 512 2371478 to 81 | Fax : +91 512 2399854/ 2332665

website: www.jkcement.com | e-mail: comp.sec@jkcement.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	CONSOLIDATED			
		Three Months Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Three Months Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	3,070.08	2,597.90	6,479.05	12,052.10
2.	Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax	450.52	285.12	1,149.08	2,043.85
3.	Net Profit for the Period before share (Loss) in associates and tax (before Exceptional and Extraordinary items)	242.72	52.65	731.86	1,139.45
4.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	242.88	155.00	732.03	1,242.39
5.	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	159.25	136.15	483.50	872.17
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	185.79	138.35	508.01	887.53
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	77.27	77.27	77.27	77.27
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	5,704.41	4,656.67	5,704.41	5,221.16
9.	Security Premium Account	756.80	756.80	756.80	756.80
10.	Net Worth	6,538.48	5,490.74	6,538.48	6,055.23
11.	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	5,139.43	4,530.26	5,139.43	4,961.33
12.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA
13.	Debt Equity Ratio	0.98	1.02	0.98	0.97
14.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Not Annualized except Period / Year ended)	20.78	16.28	62.76	111.44
15.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
16.	Debenture Redemption Reserve	-	7.50	-	3.75
17.	Debt Service Coverage Ratio	1.82	1.91	2.11	1.91
18.	Interest Service Coverage Ratio	4.77	2.65	5.87	4.86

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarter and half year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:-www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.jkcement.com.

2 Key Standalone Financial Information:

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			
		Three Months Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Three Months Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	2,907.77	2,447.33	6,153.55	11,357.23
2.	Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax	442.09	272.64	1,126.13	1,987.30
3.	Net Profit for the Period before share (Loss) in associates and tax (before Exceptional and Extraordinary items)	260.61	59.96	758.48	1,170.62
4.	Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	260.61	59.96	758.48	1,225.00
5.	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	175.78	40.47	508.26	851.27
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	174.96	40.21	506.59	847.91
7.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share)	77.27	77.27	77.27	77.27
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	5,600.33	4,601.32	5,600.33	5,209.64
9.	Security Premium Account	756.80	756.80	756.80	756.80
10.	Net Worth	6,434.40	5,435.39	6,434.40	6,043.71
11.	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	5,139.43	4,530.26	5,139.43	4,961.33
12.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA
13.	Debt Equity Ratio	0.98	1.02	0.98	0.97
14.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Not Annualized except Period / Year ended)	22.75	5.24	65.78	110.17
15.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
16.	Debenture Redemption Reserve	-	7.50	-	3.75
17.	Debt Service Coverage Ratio	1.79	1.85	2.08	1.86
18.	Interest Service Coverage Ratio	4.78	2.59	5.88	4.80

3 These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries together referred as the "Group" have been prepared in accordance with Ind AS 110 – Consolidated financial statements.

For and on behalf of the Board of Directors

Scan the QR Code to download the full financial results

Place : Gurugram
Date : 01 November, 2025

Dr. Raghavpat Singhania
Managing Director
DIN: 02426556

JKsuper PROTECT BUILD STRONG | JKsuper STRONG CONCRETE SPECIAL BUILD STRONG | JKsuper cement BUILD STRONG | JKMaxx PAINTS | JKcement WallMaxX White Cement Based Putty | JKcement WallMaxX ADVANCED Premium Wall Putty | JKcement ShieldMaxX Universal Waterproof Putty | JK CEMENT WhiteMaxX White Portland Cement | JKTYLO PREMIUM ADHESIVES & GROUTS | JKPROFIX TRUSTED BY EXPERTS

For Kind Attention of Shareholders : As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report, etc. on email.